

**¹[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर]
अधिनियम, 2020**

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020)

**[जो पूर्व में राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
अधिनियम, 2020 के नाम से जाना जाता था]**

**THE ²[MAHAYOGI GURU GORAKHNATH AYUSH
UNIVERSITY, GORAKHPUR], ACT, 2020**

(U.P. Act No. 6 of 2020)

**[Formerly known as the STATE AYUSH UNIVERSITY,
UTTAR PRADESH ACT, 2020]**

1. Subs. by sec. 2 of U.P. Act No. 6 of 2021.

2. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

1[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर]

अधिनियम, 2020²

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020]

उ०प्र० अधिनियम संख्या 6, 2021

द्वारा संशोधित

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ, “भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने दिनांक 11 मार्च, 2020 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश गजट असाधारण में दिनांक 12 मार्च, 2020 को प्रकाशित हुआ।]

उत्तर प्रदेश स्थित गोरखपुर में 1[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर] नामक एक 1[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर] की स्थापना करने तथा उससे सम्बन्धित और आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये
अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय —एक

प्रारम्भिक

1—(1) यह अधिनियम 1[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर] अधिनियम, 2020 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में है।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

2—जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

परिभाषायें

(1) ‘विद्या परिषद’ और ‘कार्य परिषद’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः विद्या परिषद और कार्य परिषद से है ;

(2) ‘सम्बद्ध महाविद्यालय’ या ‘सम्बद्ध संस्था’ का तात्पर्य इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गयी परिनिधमावली के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या किसी संस्था से है ;

(3) ‘नियत दिनांक’ का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है;

(4) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और परिचर्या के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 एवं केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1939, उत्तर प्रदेश होम्योपैथी मेडिसिन ऐक्ट, 1951 में उनके लिये समनुदेशित हैं;

(5) ‘संकाय’ का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी अध्यापन संकाय से है;

(6) ‘सरकार’ का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार से है;

1. उ० प्र० अधिनियम संख्या 6, 2021 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. उद्देश्य व कारणों हेतु इस अधिनियम के अन्त में देखें।

(7) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त छात्रों के आवास-इकाई से है;

(8) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के सम्बन्ध में 'प्रबन्धतंत्र' का तात्पर्य उस महाविद्यालय के प्रबंधन संबंधी क्रियाकलापों से प्रभारित और विश्वविद्यालय द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त प्रबन्ध समिति या अन्य निकाय से है;

(9) 'आयुष' का तात्पर्य आनुकल्पिक चिकित्सा प्रणाली की उन समस्त शाखाओं से है, जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा तथा सोयारिग्पा, परिचर्या, पराचिकित्सा विज्ञान और उनकी समस्त शाखाओं के अन्य समवर्ती विषय सम्मिलित हैं;

(10) 'विहित' का तात्पर्य परिनियमावली द्वारा विहित से है;

(11) 'परिनियमावली' 'अध्यादेशों' और 'विनियमावली' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमावली, अध्यादेशों और विनियमावली से है;

(12) 'अध्यापक' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों द्वारा अनुदेश या मार्गदर्शन प्रदान करने अथवा अनुसंधान संचालित करने के लिए नियोजित किसी अध्यापक से है, जिसमें किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निदेशक या प्राचार्य सम्मिलित है;

(13) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित ¹[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर] से है।

अध्याय—दो

विश्वविद्यालय

3—कुलाधिपति, कुलपति और कार्य परिषद तथा विद्या परिषद के सदस्यों, जो विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पदधारण करते हों, से ¹[महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर] के नाम से एक निगमित निकाय सृजित होगी।

4—(1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति, सरकार द्वारा तीन वर्ष के लिए की जायेगी।

(2) प्रतिकुलपति और चिकित्सालयों के चिकित्सा अधीक्षक (अधीक्षकों) की नियुक्ति, कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के आचार्यों के माध्यम से की जा सकती है।

5—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :—

(क) आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्धा तथा सोयारिग्पा, परिचर्या, भैषजी, पराचिकित्सा विज्ञान और उनकी समय-समय पर विहित की जाने वाली अन्य शाखाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना तथा उनमें अध्यापन, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संबंधी दक्ष एवं व्यवस्थित अनुदेश, सुनिश्चित करना;

(ख) बहुशाखीय और अतिविशिष्ट आयुष चिकित्सालयों का उपबन्ध करना;

(ग) उसके चिकित्सालयों तथा स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों का उपचार करना;

(घ) सम्बद्ध (सरकारी तथा निजी रूप से प्रबन्धकृत) महाविद्यालयों को सम्बद्ध करना, उनका पर्यवेक्षण करना तथा उन्हें विनियमित करना और तत्सम्बन्धी परीक्षाएँ संचालित करना;

विश्वविद्यालय का निगमितीकरण

कुलपति और कर्मचारीवृन्द की प्रथम नियुक्ति

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

(ड) आयुष चिकित्सालयों, निदान केन्द्रों तथा रक्त बैंकों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध एवं नियंत्रण करना;

(च) परम्परागत तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(छ) अध्यापकों और अन्य प्राविधिक तथा पराचिकित्सीय अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना; और

(ज) संघ, राज्य और अन्य अभिकरणों की विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वयीत करना।

6-विश्वविद्यालय के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे:-

**विश्वविद्यालय की
शक्तियाँ और
कृत्य कर्तव्य**

(एक) आयुष चिकित्सा, परिचर्या, परा-चिकित्सीय तथा अन्य शाखाओं जैसा कि विश्वविद्यालय उचित समझे, में अध्यापन तथा प्रशिक्षण संस्थित करना, और उन शाखाओं में अनुसंधान एवं ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के लिये उपबंध करना तथा उनकी अनुवृद्धि का प्रबंध करना;

(दो) सम्बद्ध आयुष महाविद्यालयों, परिचर्या संस्थाओं तथा परा-चिकित्सा संस्थाओं और ऐसे घटक एवं स्वशासी महाविद्यालयों में उपाधियां संस्थित करना तथा प्रदान करना;

(तीन) विश्वविद्यालय के विभिन्न आयुष पाठ्यक्रमों में छात्रों को प्रवेश का और परीक्षा या परीक्षण आयोजित करना तथा तत्सम्बंध में शर्तें अधिकथित करना;

(चार) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाएं आयोजित करना और उन्हें उपाधियां, स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ स्वीकृत करना तथा प्रदत्त करना; जो-

(क) विश्वविद्यालय या उसके सम्बद्ध महाविद्यालयों में पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन किये हों; अथवा

(ख) विश्वविद्यालय में अनुसंधान जारी रखे हों;

(पाँच) परिनियमावली में अधिकथित रीति से और उसकी शर्तों के अधीन मानद् उपाधियाँ अथवा अन्य विद्या सम्बंधी विशेष उपाधियाँ प्रदत्त करना;

(छः) अभ्यर्थियों, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, के लिये ऐसे व्याख्यानों, अनुदेशों तथा प्रशिक्षण का उपबंध करना जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे;

(सात) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकरणों के साथ, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिये, जैसाकि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार तथा सहयोग करना;

(आठ) छात्रवृत्ति, अध्येतावृत्ति, अध्ययनवृत्ति, वृत्तिका, पदक, पारितोषिक संस्थित करना तथा प्रदान करना और अन्य छात्र कल्याणकारी क्रियाकलापों का दायित्व ग्रहण करना;

(नौ) किसी उपाधि हेतु पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनार्थ किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि को अपनी उपाधि के समतुल्य या किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी समकक्ष परीक्षा को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट परीक्षा के समतुल्य मान्यता प्रदान करना;

(दस) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का पूरा करने के लिये अनुसंधान संस्थानों, चिकित्सालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों या अन्य आवश्यक बातों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रशासन करना;

(ग्यारह) छात्रावासों की स्थापना , अनुरक्षण और प्रशासन करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए आवास के स्थानों को मान्यता देना;

(बारह) फीस एवं अन्य प्रभार नियत करना और संग्रह करना;

(तेरह) निवासियों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य के संवर्द्धन के लिये व्यवस्था करना;

(चौदह) अध्यापन, प्रशासनिक, प्राविधिक, अध्यापनेत्तर और विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उन पर नियुक्तियाँ करना;

(पन्द्रह) श्रेष्ठ शोध और एकस्व कार्यों के प्रकाशन का दायित्व लेना;

(सोलह) अपने चिकित्सालयों में रोगियों के प्रबन्धन और उपचार के लिये उपबन्ध करना;

(सत्रह) किसी राजकीय या निजी आयुष महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो परिचर्या तथा पराचिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा या प्रशिक्षण प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता के विशेषाधिकार देना अथवा ऐसे विशेषाधिकारों को वापस लेना या उनमें कटौती करना और ऐसी संस्था के कार्यों का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना;

(अट्ठारह) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित ऐसे सभी कार्य एवं बातें करना चाहे वे पूर्वोक्त शक्तियों के आनुषंगिक हों या न हों।

7—(1) उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

विशेषाधिकारों
की अधिकारिता
और उनकी
स्वीकृति

(2) परिचर्या, पराचिकित्सा शाखाओं में आयुष चिकित्सा उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का कोई महाविद्यालय या संस्था किसी अन्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध नहीं की जायेगी और किसी अन्य राज्य विश्वविद्यालय के किसी भी रूप में किन्हीं विशेषाधिकारों में या उनकी स्वीकृति प्राप्त करने हेतु सरकार का अनुमोदन सम्मिलित होगा।

(3) उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी आयुष विज्ञान के किसी आयुष महाविद्यालय या संस्था द्वारा नियत दिनांक के पूर्व अन्य विश्वविद्यालय से उपभुक्त ऐसा कोई विशेषाधिकार ऐसे दिनांक से प्रत्याहृत माना जायेगा।

(4) नियत दिनांक को और से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी क्षेत्रीय राज्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों से पूर्व में स्वीकृत या उनसे सम्बद्ध आयुष चिकित्सा विज्ञान के समस्त महाविद्यालय और संस्थाएँ, इस विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों को स्वीकृत किये हुये या उससे सम्बद्ध समझे जायेंगे।

8—जाति, वर्ग, पंथ या लिंग के भेदभाव के बिना विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिये होगा, परन्तु यह कि आयुष विश्वविद्यालय—

विश्वविद्यालय
समस्त जातियों
एवं पंथों के
लिए होगा

(एक) विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता निबन्धित कर सकता है;

(दो) तत्समय प्रवृत्त सरकार के किसी विधि या आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, महिला छात्रों और अन्य श्रेणियों के पक्ष में आरक्षण कर सकता है।

निरीक्षण और जाँच

9—(1) सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जैसा कि वह निदेश दे, **परिदर्शन** विश्वविद्यालय, जिसके अन्तर्गत उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, कर्मशालायें तथा उपस्कार हैं, के सम्बंध में, और विश्वविद्यालय द्वारा कराई गयी परीक्षाओं, अध्यापन तथा समस्त अन्य कार्यों का निरीक्षण कराने का, और उसी प्रकार विश्वविद्यालय के प्रशासक तथा वित्त व्यवस्था से सम्बन्धित किसी विषय के सम्बन्ध में निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

(2) जहाँ सरकार उपधारा (1) के अधीन कोई निरीक्षण या जाँच कराने का विनिश्चय करे, तो वह उसकी सूचना कुलसचिव के माध्यम से विश्वविद्यालय को देगी और ऐसे निरीक्षण या जाँच में परिषद द्वारा नाम-निर्दिष्ट कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हो सकेगा और उसे इस रूप में सुनवाई का अधिकार होगा:

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय की ओर से विधि व्यवसायी के रूप में ऐसी निरीक्षण या जाँच में उपस्थित नहीं होगा, पक्ष समर्थन नहीं करेगा या कार्य नहीं करेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण या जाँच करने के लिये नियुक्त व्यक्ति या व्यक्तियों को, शपथ पर साक्ष्य लेने और साक्षियों को उपस्थित कराने तथा दस्तावेजों और सारवान वस्तुओं को प्रस्तुत करने के प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन समस्त शक्तियाँ होंगी और ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और 346 के अर्थान्तर्गत सिविल न्यायालय समझा जायेगा और उसके या उनके समक्ष कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाहियाँ समझी जायेंगी।

(4) सरकार ऐसे निरीक्षण या जाँच के परिणाम के प्रति निर्देश, कुलपति को सम्बोधित करेगी और कुलपति, सरकार के विचार और उस पर की जाने वाली कार्यवाही के सम्बंध में ऐसे परामर्श, जैसा कि सरकार प्रदान करे, के साथ कार्य-परिषद को संसूचित करेगी।

(5) कुलपति, तब ऐसे समय के भीतर, जिसे सरकार नियत करे कार्य परिषद द्वारा की गयी या की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की रिपोर्ट उसे प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, युक्तियुक्त समय के भीतर सरकार के समाधान के अनुसार कार्यवाही न करें तो सरकार किसी ऐसे स्पष्टीकरण पर, जिसे विश्वविद्यालय के प्राधिकारी प्रस्तुत करें, विचार करने के पश्चात् ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे और विश्वविद्यालय के प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(7) सरकार, कुलपति को उपधारा (1) के अधीन कराये गये किसी निरीक्षण या जाँच की, और उपधारा (5) के अधीन कुलपति से प्राप्त प्रत्येक संसूचना की, और उपधारा (6) के अधीन जारी किये गये प्रत्येक निदेश की प्रत्येक रिपोर्ट, और ऐसे निदेशों का अनुपालन करने अथवा न करने के सम्बंध में प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट या सूचना की प्रतियाँ भी भेजेगी।

अध्याय— तीन विश्वविद्यालय के अधिकारी

10—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :—

विश्वविद्यालय
के अधिकारी

- (क) कुलाधिपति;
- (ख) कुलपति;
- (ग) प्रति-कुलपति;
- (घ) कुलसचिव;
- (ङ) वित्त अधिकारी;
- (च) परीक्षा नियंत्रक;
- (छ) संकाय का संकायाध्यक्ष;

(ज) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायें।

11—(1) राज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रधान होंगे और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे। **कुलाधिपति**

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान करने का प्रत्येक प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अधीन होगा।

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मांगें, प्रस्तुत करें।

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उसे इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा या उनके अधीन प्रदान की जाए।

12—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतानिक अधिकारी होगा और **कुलपति** उपधारा (6) या उपधारा (10) द्वारा तथा उपबंधित के सिवाय वह कुलाधिपति द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किया जायेगा, जिनके नाम, उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा उन्हें प्रस्तुत किये गये हों।

(2) (क) केवल ऐसा व्यक्ति, कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि या अरसठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, के लिये पद धारण करेगा;

(ग) कुलपति, जिसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, इस रूप में दूसरी अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग—पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा।

(3) कुलपति की नियुक्ति, कुलाधिपति द्वारा ऐसी समिति की संस्तुति पर की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- (क) मुख्य सचिव;

(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग;

(ग) कुलपति, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून;

(घ) निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली;

(ङ) आयुष क्षेत्र में एक विशेषज्ञ, जो चिकित्सा संस्था या चिकित्सा विश्वविद्यालय के प्रधान की श्रेणी से नीचे का न हो, जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन पदावधि समाप्ति अथवा पदत्याग के कारण कुलपति के पद में होने वाली रिक्ति के दिनांक से यथाशक्य कम से कम साठ दिन पूर्व और जब कभी अपेक्षा की जाये ऐसे दिनांक के पूर्व जो कुलाधिपति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये, समिति कुलपति का पद धारण करने के लिये कुलाधिपति को कम से कम तीन और अधिक से अधिक पांच ऐसे व्यक्तियों के नाम प्रस्तुत करेगी। समिति, कुलाधिपति को नाम प्रस्तुत करते समय सिफारिश किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक की शैक्षणिक अर्हताओं का एक संक्षिप्त विवरण भी भेजेगी किन्तु वह उसमें कोई अधिमान-क्रम उपदर्शित न करेगी।

(5) जहां कुलाधिपति समिति द्वारा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक व्यक्तियों को कुलपति नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त नहीं समझते हैं अथवा संस्तुत किये गये व्यक्तियों में से एक या एकाधिक व्यक्ति नियुक्ति के लिए उपलब्ध न हों और कुलाधिपति के लिए चयन करना तीन से कम व्यक्तियों तक सीमित हो जाय तो वह समिति से उपधारा (4) के अनुसार नये नामों की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(6) समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं की जायेगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं अथवा किसी ऐसे व्यक्ति ने उसकी कार्यवाहियों में भाग लिया, जिसके संबंध में बाद में यह पाया जाय कि वह ऐसा करने का हकदार नहीं था।

(7) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जो राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त अवधारित करे।

(8) निम्नलिखित किन्हीं भी परिस्थितियों में (जिनके विद्यमान होने के एक मात्र निर्णायक स्वयं कुलाधिपति होंगे) कुलाधिपति, किसी उपयुक्त व्यक्ति को छः मास से अनधिक पदावधि के लिए, जैसा वह विनिर्दिष्ट करे, कुलपति के पद पर नियुक्त कर सकेंगे:—

(क) जहां कुलपति का पद छुट्टी लेने के कारण अथवा पद-त्याग या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से, रिक्त हो जाये अथवा उसका रिक्त होना सम्भाव्य हो, तो उसकी सूचना कुलसचिव द्वारा कुलाधिपति को तुरन्त दी जाएगी;

(ख) जहाँ कुलपति का पद रिक्त हो जाये और उसे उपधारा (1) से (5) के उपबन्धों के अनुसार सुविधा तथा शीघ्रता से भरा न जा सकता हो;

(ग) किसी अन्य आपात स्थिति में :

परन्तु कुलाधिपति इस उपधारा के अधीन कुलपति पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की पदावधि को, समय-समय पर बढ़ा सकेंगे। किन्तु इस प्रकार की ऐसी नियुक्ति की कुल पदावधि (जिसके अन्तर्गत मूल आदेश में नियत अवधि भी है) एक वर्ष से अधिक न हो।

(9) जब तक कि उपधारा (1) या उपधारा (5) या उपधारा (8) के अधीन नियुक्त कुलपति अपने पद का कार्यभार न संभाल ले तब तक प्रतिकुलपति, यदि कोई हो, या जहाँ कोई प्रतिकुलपति न हो, वहाँ विश्वविद्यालय का ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का भी निर्वहन करेगा।

(10) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को यह अन्यथा प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिये अहितकर है, तो कुलाधिपति ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वह उचित समझे, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(11) उपधारा (10) में निर्दिष्ट किसी जांच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जांच को अनुध्यात करते हुए कुलाधिपति यह आदेश दे सकते हैं कि अग्रतर आदेशों तक—

(क) ऐसा कुलपति, कुलपति के पद के कार्य संचालन से विरत रहेगा, किन्तु उसे ऐसी परिलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये वह अन्यथा उपधारा (7) के अधीन हकदार था;

(ख) कुलपति के पद के कृत्यों का सम्पादन, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।

13—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक तथा शैक्षणिक अधिकारी होगा, और —

कुलपति की शक्तियाँ तथा कर्तव्य

(क) विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रवर्तित करेगा;

(ग) कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, प्राधिकारियों के अधिवेशनों और विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा;

(घ) नए छात्रों का उनके ज्येष्ठों द्वारा किसी हिंसक या अशोभनीय रैगिंग के प्रतिषेध को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा;

(ङ) विश्वविद्यालय परीक्षाओं का समुचित ढंग से और ठीक समय पर आयोजन और संचालन करने के लिये और यह सुनिश्चित करने के लिये कि ऐसी परीक्षाओं का परीक्षाफल शीघ्रता से प्रकाशित किया जाता है और विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र समुचित दिनांक को प्रारम्भ एवं समाप्त होता है, उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति का पदेन सदस्य और अध्यक्ष (अध्यक्षा) होंगे/होंगी।

(3) कुलपति को विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के अधिवेशन में बोलने और अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु इस उपधारा के आधार पर मत देने का हकदार नहीं होगा।

(4) कुलपति का कर्तव्य होगा कि वह इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठापूर्वक अनुपालन किया जाना सुनिश्चित करे और धारा 11 और 50 के अधीन कुलाधिपति की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे ऐसी सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो उस निमित्त, आवश्यक हों।

(5) कुलपति को कार्य परिषद, विद्या परिषद तथा वित्त समिति की बैठकें बुलाने अथवा बुलवाने की शक्ति होगी :

परन्तु कुलपति विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिकारी को इस उपधारा के अधीन अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(6) जहां विश्वविद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसी अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा उस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गई कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट, वह कुलाधिपति तथा ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी अथवा अन्य निकाय को भी देगा जो साधारण क्रम में उक्त मामले के सम्बन्ध में कार्यवाही करते :

परन्तु यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की यह राय हो कि ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा अथवा उसे ऐसी रीति से उपान्तरित करेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप से प्रभावी होगी तथापि ऐसे निष्प्रभावीकरण या उपांतर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही के विरुद्ध उस दिनांक से, जिस दिनांक को ऐसी कार्यवाही पर विनिश्चय से उसे संसूचित किया जाए, अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त कार्य परिषद, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगी या उसे उलट सकेगी।

(7) उपधारा (6) में किसी बात से कुलपति का कोई ऐसा व्यय उपगत करने के लिये सशक्त नहीं समझा जायेगा जो सम्यक् रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था, बजट में न की गयी हो।

(8) जहाँ उपधारा (6) के अधीन कुलपति द्वारा शक्ति के प्रयोग में नियुक्ति सम्मिलित हो, वहाँ ऐसी नियुक्ति, उक्त विहित रीति से नियुक्ति किये जाने पर अथवा कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जायेगी।

(9) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि परिनियमों और अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किया जाय।

14—(1) कुलपति, यदि आवश्यक समझे विश्वविद्यालय के आचार्यों में से किसी प्रति—कुलपति एक को प्रति—कुलपति नियुक्त कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रति—कुलपति, आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(3) प्रति कुलपति, कुलपति के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेगा।

(4) प्रति कुलपति, सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा यथा अवधारित धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा।

(5) प्रति—कुलपति ऐसे मामलों में कुलपति की सहायता करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा समय—समय पर इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाय तथा वह कुलपति की अनुपस्थिति में विश्वविद्यालय के बैठकों का सभापतित्व करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जैसाकि कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित या प्रत्यायोजित किया जाय।

15—(1) कुल सचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

कुल सचिव

(2) कुल सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा ऐसे निबंधनो और शर्तों पर की जायेगी जैसाकि विहित किया जाय।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेख अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी।

(4) कुल सचिव विश्वविद्यालय के अभिलेखों और सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह किसी अध्यापक हेतु कार्य परिषद, विद्या परिषद, प्रवेश समिति, अनुशासन समिति का और विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति और पदोन्नति हेतु प्रत्येक चयन समिति का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों तथा कुलपति के समक्ष समय—समय पर अपेक्षित ऐसी समस्त सूचनाओं को रखने के लिये बाध्य होगा किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) कुल सचिव को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक न तो प्रदान किया जायेगा और न वह स्वीकार करेगा।

(6) सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर सहायता देने और सहायता करने के लिये उप कुलसचिव (उप कुलसचिवों) तथा सहायक कुल सचिव (सहायक कुल सचिवों) की नियुक्ति की जा सकती है।

16—(1) विश्वविद्यालय हेतु एक वित्त अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति सरकार द्वारा एक अधिसूचना द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

वित्त अधिकारी

(2) सरकार द्वारा स्वीकृत सदस्य संख्या के सापेक्ष, परिनियमावली के अधीन विहित शर्तों पर वित्त अधिकारी को सहायता देने और सहायता करने के लिये एक लेखा अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है।

(3) वित्त अधिकारी कार्य परिषद को बजट (वार्षिक प्राक्कलन) और लेखा विवरण प्रस्तुत करने तथा विश्वविद्यालय की ओर से निधियों का आहरण एवं वितरण करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।

(4) वित्त अधिकारी को कार्य परिषद की कार्यवाहियों में बोलने और उनमें अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु वह मत देने का हकदार नहीं होगा।

(5) वित्त अधिकारी निम्नलिखित के लिये उत्तरदायी होगा :-

(क) यह सुनिश्चित करना है कि विश्वविद्यालय द्वारा (विनिधान से भिन्न) बजट में अप्राधिकृत कोई व्यय उपगत न किया जाए;

(ख) किसी ऐसे प्रस्तावित व्यय को अस्वीकार करना जो इस अधिनियम के उपबंधों या किन्हीं परिणियमों या अध्यादेशों के निबन्धनों का उल्लंघन करता हो;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि कोई अन्य वित्तीय अनियमितता न की जाय और लेखा-परीक्षा के दौरान उपदर्शित किन्हीं अनियमितताओं को ठीक करने के लिये कदम उठाये जाएं;

(घ) यह सुनिश्चित कराना कि विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा उसके विनिधानों को सम्यक रूप से संरक्षण और प्रबंध किया जाय।

(6) वित्त अधिकारी की पहुंच विश्वविद्यालय के ऐसे अभिलेखों और दस्तावेजों तक होगी तथा वह उन्हें प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और उसकी राय में उसके कार्यों से सम्बन्धित ऐसी सूचना का प्रस्तुत किया जाना उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आवश्यक हो सकता है।

(7) वित्त अधिकारी को विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु कोई पारिश्रमिक न तो दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(8) वित्त अधिकारी विश्वविद्यालय की ओर से समस्त संविदायें करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा।

(9) वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियां और कृत्य ऐसे होंगे जैसाकि विहित किया जाय।

17-(1) परीक्षा नियंत्रक विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा।

परीक्षा नियंत्रक

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जायेगी और उसके पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय, विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक अपने कार्य से संबंधित अभिलेखों की सम्यक अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा। वह विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति का पदेन सचिव होगा और वह ऐसी समिति के समक्ष ऐसी समस्त सूचनायें प्रस्तुत करने के लिये उत्तरदायी होगा जैसा कि उसके कारबार के संव्यवहार के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी सम्पादन करेगा जैसा कि विनियमों और अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या जैसा कि कार्य परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाय किन्तु वह इस उपधारा के आधार पर मत देने के लिये हकदार नहीं होगा।

(4) परीक्षा नियंत्रक को अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना होगा और उसके पास इस संबंध में कुल सचिव की समस्त शक्तियां होंगी।

(5) परीक्षा समिति के अधीक्षण के अध्याधीन परीक्षा नियंत्रक को परीक्षाओं का संचालन करना होगा और उसके लिये समस्त अन्य व्यवस्थाएँ करनी होंगी और तत्सम्बन्धी समस्त प्रक्रियाओं के सम्यक निष्पादन हेतु उत्तरदायी होगा।

(6) परीक्षा नियंत्रक को सरकार के आदेश के सिवाय विश्वविद्यालय में किसी कार्य हेतु न तो कोई पारिश्रमिक दिया जायेगा और न ही वह स्वीकार करेगा।

(7) जहां परीक्षा नियंत्रक, किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ हो या परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन, यथा स्थिति, परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्त हो तो उस पद के समस्त कर्तव्यों का सम्पादन, परीक्षा नियंत्रक के पुनः अपने कर्तव्यों को संभालने तक या रिक्ति को भरे जाने तक कुलपति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया जायेगा।

(8) अतिरिक्त परीक्षा नियंत्रक और उप परीक्षा नियंत्रक को सरकार द्वारा अनुमोदित सदस्य संख्या के सापेक्ष परिनियमों के अधीन विहित शर्तों पर परीक्षा नियंत्रक को सहायता देने और सहायता करने के लिये नियुक्त किया जा सकता है।

18—कुलाधिपति, कुलपति, प्रति-कुलपति, वित्त अधिकारी, कुल सचिव और अन्य अधिकारी परीक्षा नियंत्रक, यदि कोई हों, जो नियुक्त किये गये हों, से भिन्न विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्ति वही होगी जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाय या अधिकथित किया जाय।

अध्याय — चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

19—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात्:—

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

- (क) कार्य परिषद;
- (ख) विद्या परिषद;
- (ग) वित्त समिति;
- (घ) परीक्षा समिति;
- (ङ) संकाय बोर्ड;
- (च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति हेतु चयन समिति;
- (छ) प्रवेश समिति;

(ज) ऐसे अन्य प्राधिकारी, जिन्हें परिनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकारी घोषित किया जाय।

20—(1) कार्य परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

कार्य परिषद का गठन

(क) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होंगी;

(ख) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;

(ग) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आयुष विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती, जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(घ) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग अथवा उसका नामनिर्देशिती जो विशेष सचिव की श्रेणी से नीचे का न हो;

(ङ) सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के दो संकायों के संकायाध्यक्ष ज्येष्ठता क्रम में चक्रानुक्रम द्वारा;

- (च) निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उत्तर प्रदेश;
- (छ) निदेशक, आयुर्वेद (पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन), उत्तर प्रदेश;
- (ज) निदेशक, यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
- (झ) निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ;
- (ञ) कार्य परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट राजकीय आयुष महाविद्यालयों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य;
- (ट) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक राजकीय आयुष महाविद्यालय का एक प्राचार्य;
- (ठ) सम्बद्ध महाविद्यालयों सहित विश्वविद्यालय के दो ज्येष्ठ आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ड) आयुष चिकित्सा व्यवसाय या सामाजिक सेवा में संलग्न सिविल सोसाइटी के दो प्रख्यात सदस्य या सेवानिवृत्त सिविल सेवक या सेवानिवृत्त न्यायाधीश, जो सरकार की संस्तुति पर कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(2) कार्य परिषद के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) कोई व्यक्ति कार्यपरिषद का सदस्य होने और सदस्य (पदेन सदस्य से भिन्न) रहने के लिए अनर्ह होगा, यदि वह या उसका नातेदार विश्वविद्यालय अथवा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय की सेवा में होंगे अथवा विश्वविद्यालय में या उसके लिये किसी कार्य के लिये कोई पारिश्रमिक अथवा विश्वविद्यालय को माल की आपूर्ति करने की, या उसके निमित्त किसी कार्य का निष्पादन करने की कोई संविदा स्वीकार करता है:

परन्तु यह कि इस उपधारा की कोई बात, किसी अध्यापक द्वारा इस रूप में अथवा विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिये अथवा किसी प्रशिक्षण के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों का पालन करने के लिए अथवा किसी प्रशिक्षण इकाई या किसी छात्रावास के अधीक्षक या वार्डन अथवा प्राक्टर के रूप में किन्हीं कर्तव्यों के लिये अथवा विश्वविद्यालय के संबंध में तत्सदृश किन्हीं कर्तव्यों के लिये कोई पारिश्रमिक स्वीकार करने पर लागू न होगी।

स्पष्टीकरण— इस धारा में नातेदार का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013, की धारा 2 में परिभाषित कम्पनी और परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देशन नियम, 2014 के नियम-4 के अधीन विहित “नातेदारों” से है।

21—(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान कार्यकारी निकाय होगी और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए उसकी निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात्:—

कार्य परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य

(एक) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधियों को धारण करना और उन पर नियंत्रण रखना;

(दो) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अर्जन या अन्तरण करना;

(तीन) परिनियमों और अध्यादेशों को बनाना, संशोधित करना या निरसित करना;

(चार) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिये विश्वविद्यालय के व्ययन पर रखी गई किन्हीं निधियों को प्रशासित करना;

(पाँच) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(छः) अध्यादेशों के अनुसार छात्रवृत्तियाँ, अधि-छात्रवृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक और अन्य पारितोषिक प्रदान करना;

(सात) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करना और उनके कर्तव्यों और उनकी सेवा की शर्तों को परिभाषित करना और उनके पदों की अस्थायी आकस्मिक रिक्तियों को भरने की व्यवस्था करना;

(आठ) परीक्षकों की फीस, परिलब्धियाँ तथा यात्रा और अन्य भत्ते नियत करना;

(नौ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा का आकार और उसके प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देना;

(दस) विश्वविद्यालय के अध्यापक वर्ग, प्रशासकीय वर्ग और अन्य कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के मध्य परिनियमों और अन्य अध्यादेशों के अनुसार अनुशासन विनियमित और प्रवर्तित करना;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, सम्पत्ति, कारोबार और अन्य सभी प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उक्त प्रयोजन के लिये ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना, जिन्हें वह ठीक समझे;

(बारह) विश्वविद्यालय के किसी धन को (जिसके अन्तर्गत किसी न्यास या विन्यासित सम्पत्ति से होने वाली कोई आय भी है) ऐसे स्टाक निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में, जिन्हें वह समय-समय पर ठीक समझे या भारत में स्थावर सम्पत्ति को क्रय करने में विनिधान करना और समय-समय पर ऐसे विनिधान में परिवर्तन करना;

(तेरह) विश्वविद्यालय के कार्य को करने के लिये आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र और अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(चौदह) विश्वविद्यालय की ओर से संविदा करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और निरस्त करना;

(पन्द्रह) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय और साथ ही साथ घटक, सम्बद्ध महाविद्यालयों, चिकित्सालयों और स्वास्थ्य केन्द्रों से सम्बन्धित अन्य सभी विषयों को विनियमित करना और अवधारित करना।

(2) सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना कार्य परिषद, बन्धक, विक्रय, विनिमय, दान या अन्यथा द्वारा विश्वविद्यालय की किसी स्थावर सम्पत्ति का (सिवाय साधारण प्रबन्ध के अनुक्रम में मासानुसार किराये पर देने के) न तो अन्तरण करेगी और न सिवाय सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार से विश्वविद्यालय के लिये कोई सहायता अनुदान प्राप्त होने की शर्त के रूप में अथवा सरकार के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति से उसकी प्रतिभूति पर कोई धन उधार या अग्रिम लेगी।

(3) सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त किये बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जायेगा जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा ऐसा अनुमोदन अपेक्षित हो और सरकार के पूर्वानुमोदन के सिवाय अथवा सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के सिवाय कोई भी पद विश्वविद्यालय में सृजित नहीं किया जायेगा।

(4) विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्ते वहीं होंगे जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किये जायें।

(5) कार्य परिषद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवर्ती और अनावर्ती व्यय के लिये वित्त समिति द्वारा नियत सीमा से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगी।

(6) विद्या परिषद और सम्बन्धित संकायों के बोर्डों के परामर्श पर विचार किये बिना कार्य परिषद अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों और परीक्षकों को संदेय फीस के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(7) कार्य परिषद परिनियमों में अधिकथित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी कोई शक्ति, जिसे वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

22—(1) विद्या परिषद, विश्वविद्यालय की प्रधान विद्या निकाय होगी और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुए,—

विद्या परिषद

(क) विश्वविद्यालय में दिये जाने वाले अनुदेश, शिक्षा और किये जाने वाले अनुसंधान कार्य के स्तर को बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी और उसका नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी;

(ख) विद्या सम्बन्धी समस्त विषयों पर, जिनके अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं से सम्बन्धित विषय भी है, कार्य परिषद को परामर्श दे सकेगी; और

(ग) उसकी ऐसी अन्य शक्तियाँ तथा कर्तव्य होंगे जो उसे परिनियमों द्वारा प्रदत्त हो या उस पर अधिरोपित किये जायें।

(2) विद्या परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(एक) कुलपति;

(दो) संकायों के संकायाध्यक्ष

(तीन) विश्वविद्यालय के सभी अन्य विभागाध्यक्ष;

(चार) विश्वविद्यालय के सभी आचार्य, जो विभागाध्यक्ष न हों;

(पाँच) आयुष संस्थाओं या आयुष महाविद्यालयों के दो सेवानिवृत्त प्राचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे;

(छ:) विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्रत्येक संकाय से दो आचार्य, दो सह-आचार्य और दो सहायक आचार्य, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे; और

(सात) शैक्षणिक ख्याति के पाँच व्यक्ति, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाएंगे।

(3) नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि दो वर्ष होगी।

23—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे:—

वित्त समिति

(क) कुलपति, जो उसका/उसकी अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष विभाग का अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव;

- (ग) सरकार के वित्त विभाग का प्रमुख सचिव;
- (घ) प्रति-कुलपति, यदि कोई हो;
- (ङ) कुल सचिव;
- (च) परीक्षा नियंत्रक;
- (छ) वित्त अधिकारी जो समिति का सचिव होगा।

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) में निर्दिष्ट कोई सदस्य वित्त समिति की किसी बैठक में स्वयं भाग लेने के बजाय राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त कर सकता है और इस प्रकार प्रतिनियुक्त अधिकारी को मत देने का भी अधिकार होगा।

(3) वित्त समिति, कार्य परिषद को विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर सलाह देगी। वह विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों को ध्यान में रखते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्ती तथा अनावर्ती व्ययों की सीमा नियत करेगी और किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष के दौरान इस प्रकार नियत व्ययों की सीमा को पुनरीक्षित कर सकेगी और इस प्रकार नियत सीमा कार्य परिषद पर बाध्यकारी होगी।

(4) वित्तीय समिति को ऐसी अन्य शक्तियां तथा कर्तव्य होंगे जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा उसे प्रदत्त हों अथवा उस पर अधिरोपित किये जाएं।

24—(1) विश्वविद्यालय में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, परिचर्या, पराचिकित्सा संकाय संकाय और यथाविहित अन्य संकाय होंगे।

(2) प्रत्येक संकाय में अध्यापन के ऐसे विभाग समाविष्ट होंगे जो विहित किये जाएं और प्रत्येक विभाग में ऐसे पाठ्य विषय होंगे जो उसके लिये अध्यादेशों द्वारा समनुदेशित किये जाएं।

(3) प्रत्येक संकाय का एक बोर्ड होगा, जिसका गठन (उसके सदस्यों की पदावधि सहित) तथा उसकी शक्तियां और कर्तव्य वही होंगे जैसा कि विहित किये जायें।

(4) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो आचार्यों में से चक्रानुक्रम द्वारा ज्येष्ठता क्रम में चुना जायेगा और तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(5) संकायाध्यक्ष संकाय के बोर्ड का/की अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी, और

(क) संकाय में समाविष्ट विभागों के अध्यापन तथा अनुसंधान कार्य के संगठन तथा संचालन के लिए;

(ख) संकाय से सम्बन्धित परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के लिए;

उत्तरदायी होगा।

(6) विश्वविद्यालय में प्रत्येक अध्यापन विभाग में एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति परिनियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

(7) विभागाध्यक्ष विभाग में अध्यापन के संगठन के लिए संकायाध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होगा और उसके पास ऐसी शक्तियां और कर्तव्य होंगे जैसा कि अध्यादेशों में उपबन्धित किया जाए।

(8) विभिन्न पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में अध्ययन बोर्डों का गठन अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा और एक अध्ययन बोर्ड के लिये एक से अधिक विषय समनुदेशित किये जा सकेंगे।

25—(1) विश्वविद्यालय की एक प्रवेश समिति होगी, जिसका गठन उसी प्रकार से **प्रवेश समिति** किया जायेगा जैसा कि अध्यादेशों में उपबंधित किया गया हो।

(2) प्रवेश समिति को उतनी संख्या में उपसमितियां नियत करने की शक्तियां होगी जितनी वह ठीक समझे।

(3) विद्या परिषद के अधीक्षण के अधीन तथा उपधारा (5) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रवेश समिति विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की नीतियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों या प्रतिमानों को अधिकथित करेगी।

(4) उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए समिति प्रवेशों के मापदण्ड या पद्धतियों (जिसमें प्रवेश किये जाने वाले छात्रों की संख्या सम्मिलित हो) के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी कर सकती है।

(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के प्रवेश के लिए (अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर) ऐसी विधि या आदेशों द्वारा स्थान आरक्षित और विनियमित किये जा सकेंगे जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त करें।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश केन्द्रीय या राज्य नियामक निकायों के किन्हीं आदेशों के अधधीन होंगे।

(7) इस धारा के उपबन्धों का उल्लंघन करके विश्वविद्यालय या उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में प्रविष्ट किसी छात्र को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित किसी परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी और कुलपति के पास ऐसा उल्लंघन किये जाने पर दिये गये किसी प्रवेश को रद्द करने की शक्ति होगी।

26—(1) विश्वविद्यालय में एक परीक्षा समिति होगी, जिसका गठन अध्यादेशों में **परीक्षा समिति** यथा उपबंधित रूप में किया जायेगा।

(2) समिति सामान्यतः विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाओं का जिसमें अनुसीमन तथा सारणीकरण भी सम्मिलित है, पर्यवेक्षण करेगी और निम्नलिखित अन्य कृत्यों को सम्पादित करेगी, अर्थात्:—

(क) परीक्षकों तथा अनुसीमकों को नियुक्त करना तथा यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना;

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणामों का समय-समय पर पुनरीक्षण करना और तत्सम्बन्ध में विद्या परिषद को रिपोर्ट प्रस्तुत करना;

(ग) परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए विद्या परिषद को संस्तुतियां करना;

(घ) अध्ययन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परीक्षकों की सूची की संवीक्षा करना, उसे अंतिम रूप देना और विश्वविद्यालय के परिणामों की घोषणा करना।

(3) परीक्षा समिति उतनी उप समितियां नियुक्त कर सकेगी जितनी वह उचित समझे और विशिष्टतः किसी एक या अधिक व्यक्तियों अथवा उप समितियों को परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने से सम्बन्धित मामलों में कार्यवाही करने तथा उन पर विनिश्चय करने की शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी।

(4) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी परीक्षा समिति या यथास्थिति किसी उप समिति या किसी व्यक्ति के लिए, जिसे परीक्षा समिति ने उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त अपनी शक्ति का प्रत्यायोजन किया हो, विश्वविद्यालय की भावी परीक्षाओं से किसी परीक्षार्थी को विवर्जित करना विधिपूर्ण होगा, यदि उसकी राय में ऐसा परीक्षार्थी किसी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने का दोषी हो।

27—विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य वहीं होंगे जो विहित किये जायें। अन्य प्राधिकरण

अध्याय — पाँच

महाविद्यालयों की सम्बद्धता और मान्यता

28—(1) कार्य परिषद, किसी महाविद्यालय को, जो सम्बद्धता की उन शर्तों की पूर्ति करता है, जिन्हें विहित किया जाए, सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रदान कर सकेगी अथवा पहले से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के विशेषाधिकारों को निस्तारित कर सकेगी अथवा उपधारा (7) के उपबन्धों के अधीन ऐसे किसी विशेषाधिकार को वापस ले सकेगी या उसे कम कर सकेगी। सम्बद्ध
महाविद्यालय

(2) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह उसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित किसी अन्य सम्बद्ध महाविद्यालय के साथ अथवा विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए प्रबन्ध करे।

(3) इस अधिनियम में यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबंधतंत्र महाविद्यालय के कार्यकलापों का प्रबन्ध करने और उनका नियंत्रण करने के लिए स्वतन्त्र होगा और उसके अनुरक्षण एवं रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य, उसके विद्यार्थियों के अनुशासन के लिए और उसके कर्मचारिवृन्द पर अधीक्षण एवं नियंत्रण करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(4) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसी रिपोर्टों, विवरणियों और अन्य विशिष्टियों को प्रदान करेगा जिन्हें कार्यपरिषद अथवा उप-कुलपति मांगे।

(5) कार्यपरिषद, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगी और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जाएगी।

(6) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाही करने का निदेश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाए, आवश्यक प्रतीत हो।

(7) ऐसे किसी महाविद्यालय, जो उपधारा (6) के अधीन कार्यपरिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल हो जाता है, की सम्बद्धता का विशेषाधिकार, उस महाविद्यालय के प्रबंधतंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से, कार्यपरिषद द्वारा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिये जा सकेंगे या उनमें कमी की जा सकेगी।

(8) उपधारा (1) और (7) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए, यदि सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, सम्बद्धता की शर्तों का पालन करने में विफल हो गया हो तो कुलाधिपति प्रबन्धतंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को वापस ले सकेगा अथवा उनमें कमी कर सकेगा।

29—(1) संघटक महाविद्यालय वे महाविद्यालय होंगे, जिन्हें परिनियमों द्वारा नामित किया जाये और विश्वविद्यालय द्वारा अथवा सरकार द्वारा अनुरक्षित किये जायेंगे।

**संघटक
महाविद्यालय**

(2) किसी संघटक महाविद्यालय के प्राचार्य का महाविद्यालय के कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण होगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जैसा कि विहित किया जाय।

30—विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर, ऐसे किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को विहित रीति से स्वशासी महाविद्यालय, जो उस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करता हो, के रूप में उस महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने और इस प्रकार परिवर्तित किये गये पाठ्यक्रमों में परीक्षा आयोजित कराने के विशेषाधिकार प्रदान कर सकता है।

**स्वशासी
महाविद्यालय**

अध्याय — छः

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की भर्ती तथा उनकी सेवा की शर्तें

31—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यापक, कार्यपरिषद द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर एतदपश्चात् उपबन्धित रीति से नियुक्त किये जायेंगे। चयन समिति की बैठक उतनी बार होगी जितनी आवश्यक हो:

**अध्यापकों की
नियुक्ति**

परन्तु, अध्यापकों को किसी नियामक निकाय की अनुज्ञा की गम्भीर आवश्यकता होने पर विशेष परिस्थितियों में अनधिक एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा के आधार पर लगाया जा सकता है। न्यूनतम अर्हताएं और अनुभव वही होंगे जैसा कि सरकार के मार्गदर्शनों के अनुसार विहित की जाएं।

(2) प्रत्येक ऐसे अध्यापक की नियुक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन की गयी नियुक्ति न हो, प्रथमतः एक वर्ष के लिए परीक्षा पर होगी जिसे कार्यपरिषद द्वारा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह कि परीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा समाप्ति का कोई आदेश, विश्वविद्यालय के अध्यापक की दशा में पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि कुलपति और सम्बद्ध विभागाध्यक्ष (जब तक कि अध्यापक स्वयं विभागाध्यक्ष न हो) की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् कार्यपरिषद आदेश न दे दें:

परन्तु यह और कि सम्बद्ध अध्यापक को प्रस्तावित सेवा समाप्ति के आधारों के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण का अवसर देते हुए नोटिस दिये बिना सेवा समाप्ति का ऐसा कोई आदेश नहीं पारित किया जायेगा:

परन्तु यह भी यदि यथास्थिति परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व नोटिस दी जाए तो परीक्षा अवधि तब तक के लिए बढ़ायी जायेगी जब तक कि प्रथम परन्तुक के अधीन कार्य परिषद का अंतिम आदेश न दे दिया जाये।

(3) जहां कोई अध्यापक (चयन समिति को निर्देश देने के पश्चात्) ऐसे अस्थायी पद पर नियुक्त किया गया हो, जिसके छः मास से अधिक चलने की संभावना रही हो, और जिस पद को बाद में स्थायी पद में परिवर्तित कर दिया गया हो, या किसी स्थायी पद पर ऐसी रिक्ति में नियुक्त किया गया हो, जो पदधारी को दस मास से अधिक अवधि के लिए छुट्टी देने के कारण हुई हो और ऐसा पद बाद में स्थायी रूप से रिक्त हो जाये या उसी विभाग में उसी संवर्ग और श्रेणी का कोई अन्य पद रिक्त या नव सृजित हो जाय, वहां कार्य परिषद, यदि कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसकी सेवा समाप्त करने का विनिश्चय नहीं करती है तो ऐसे अध्यापक को उस पद पर मौलिक हैसियत से चयन समिति को निर्देश के बिना नियुक्त कर सकेगी:

परन्तु यह खण्ड तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि संबंधित अध्यापक, ऐसी मौलिक नियुक्ति के समय, उस पद के लिए विहित अर्हतायें धारण न करता हो और चयन समिति को निर्देश के पश्चात् हुई नियुक्ति के बाद उसने लगातार एक वर्ष तक काम न किया हो:

परन्तु यह और कि इस खण्ड के अधीन मौलिक हैसियत से नियुक्त कोई ऐसा अध्यापक जिसने ऐसी नियुक्ति के पूर्व दो वर्ष से कम अवधि पर्यन्त लगातार काम किया हो एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, और उपधारा (2) के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

(4) अध्यापक की नियुक्ति के लिये चयन समिति में निम्नलिखित होंगे:—

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष (अध्यक्षा) होगा/होगी;

(दो) संबद्ध विभागाध्यक्ष :

परन्तु विभागाध्यक्ष उस दशा में चयन समिति में नहीं बैठेगा जब वह स्वयं नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी हो अथवा जब सम्बद्ध पद उसके मौलिक पद की श्रेणी से उच्चतर हो, ऐसी दशा में उसका पद विभाग के ज्येष्ठतम आचार्य द्वारा और यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां कुलाधिपति का यह समाधान हो जाये कि मामले की विशेष परिस्थितियों में, पूर्ववर्ती परन्तुक के अनुसार चयन समिति का गठन नहीं किया जा सकता है, वहां वे ऐसी रीति से चयन समिति का गठन करने का निदेश दे सकते हैं, जैसी वे उचित समझें।

(तीन) किसी आचार्य या किसी सह आचार्य की दशा में तीन विशेषज्ञ, और किसी अन्य दशा में दो विशेषज्ञ, जो कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(5) (क) प्रत्येक पाठ्य विषय के लिए भारतीय विश्वविद्यालय के तत्स्थानिक संकाय या उत्तर प्रदेश में अथवा उसके बाहर स्थित ऐसे विद्या निकायों या अनुसंधान संस्थाओं से जिन्हें कुलपति आवश्यक समझें, परामर्श करने के पश्चात् कुलाधिपति छः या उससे अधिक विशेषज्ञों का एक पैनल बनायेंगे। उपधारा (4) के अधीन कुलाधिपति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जाने वाला प्रत्येक विशेषज्ञ वही व्यक्ति होगा जिसका नाम ऐसे पैनल में दिया गया हो;

(ख) खण्ड (क) में निर्दिष्ट कोई पैनल प्रत्येक तीन वर्ष के पश्चात् पुनरीक्षित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण (1) इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे विषय की शाखा को, जिसमें स्नातकोत्तर उपधि के लिए पृथक पाठ्यक्रम विहित हो, पृथक पाठ्य विषय समझा जायेगा।

स्पष्टीकरण— (2) जहां चयन किए जाने वाले अध्यापक का पद एक से अधिक पाठ्य विषय के लिए हो तो विशेषज्ञ उनमें से किसी एक पाठ्य विषय का हो सकेगा।

(ग) कुलाधिपति, चयन समिति में अपने नाम—निर्देशितियों के रूप में कार्य करने के लिए विशेषज्ञों के उतने नामों से अधिक नाम, जो उपधारा (4) के अधीन अपेक्षित हैं, विनिर्दिष्ट आदेश से संसूचित कर सकेगा। ऐसे मामले में जब कोई व्यक्ति जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में ऊपर दिया गया हो, चयन समिति की बैठक के लिए उपलब्ध न हो तो उस व्यक्ति से, जिसका नाम विनिर्दिष्ट क्रम में उसके ठीक नीचे हो, समिति में कार्य करने के लिए अनुरोध किया जायेगा;

(6) उपधारा (4) में निर्दिष्ट चयन समिति द्वारा की गयी किसी सिफारिश को तब तक विधिमान्य नहीं समझा जायेगा जब तक कि विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ ऐसे चयन से सहमत न हो;

(7) उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी चयन समिति की कुल सदस्यों के बहुमत से ऐसी समिति की गणपूर्ति होगी:

परन्तु आचार्य या सह आचार्य के मामले में गणपूर्ति के लिए उपस्थित व्यक्तियों में कम से कम दो विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।

(8) यह चयन समिति पर निर्भर होगा कि वह प्रत्येक पद के लिए एक या एक से अधिक किन्तु तीन से अनधिक नामों की सिफारिश करे।

(9) किसी अध्यापक की नियुक्ति की दशा में यदि कार्य परिषद चयन समिति द्वारा की गयी सिफारिश से सहमत न हो तो कार्यपरिषद उस मामले को असहमति के कारणों सहित कुलाधिपति को निर्दिष्ट करेगा और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद चयन समिति के अधिवेशन के दिनांक से चार मास की अवधि के भीतर समिति की सिफारिशों पर विनिश्चय न करें, तब भी मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट माना जायेगा, और उनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(10) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये चयन समिति के सदस्यों की ऐसी समितियों में विचार—विमर्श में भाग लेने में हित होने के आधार पर अनर्हता, और ऐसे अध्यापकों की नियुक्ति से संबंधित अन्य विषय, परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।

(11) इस धारा के अधीन किसी नियुक्ति के लिए चयन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वह रिक्ति कम से कम दो ऐसे समाचार-पत्रों के तीन अंकों में विज्ञापित न कर दी जाये, जिसका उत्तर प्रदेश में पर्याप्त परिचालन हो।

32—(1) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय में मौलिक रूप से नियुक्त कोई सहायक आचार्य या मौलिक रूप से नियुक्त या इस धारा के अधीन पदोन्नत कोई सह—आचार्य, जिसकी उतनी सेवा अवधि हो और जो ऐसी अर्हताएं रखता हो, जैसी विहित की जायें, को क्रमशः सह आचार्य या आचार्य के पद पर वैयक्तिक पदोन्नति दी जा सकेगी।

सह— आचार्य
और आचार्य के
पद पर
वैयक्तिक
पदोन्नति

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसी वैयक्तिक पदोन्नति, महाविद्यालय के अध्यापकों से भिन्न विश्वविद्यालय के अध्यापकों को धारा 31 की उपधारा (4) के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिश पर ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों, जैसी विहित की जायें, के अध्यधीन प्रदान की जायेगी।

33—(1) परिनियमों द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों का कोई अध्यापक, सिवाय ऐसी लिखित संविदा के, जो इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप होगी, नियुक्त नहीं किया जायेगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति की संविदा

(2) मूल संविदा कुलसचिव के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को दी जाएगी।

(3) किसी संविदा या अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, ऐसी सीमा, यदि कोई हो, के सिवाय और ऐसी शर्तों और निबन्धों के अधीन रहते हुए जैसा राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, निजी चिकित्सा व्यवसाय (प्रेक्टिस) करने का अधिकार नहीं होगा।

34—विश्वविद्यालय, अपने अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो सरकार द्वारा सामान्य और विशेष आदेश द्वारा विहित की जाएं, ऐसी पेंशन स्कीमें, बीमा या भविष्य निधि गठित करेगा, जिसे वह ठीक समझे, जिसके अन्तर्गत ऐसी निधि भी है, जिससे यथास्थिति ऐसे अध्यापकों या उनके उत्तराधिकारियों को, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (परीक्षा संचालन संबंधी उपबन्ध) अधिनियम, 1965 के अधीन अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के संबंध में उपगत निर्योग्यता, आहत या मृत्यु हो जाने की दशा में पेंशन या उपदान दिया जाएगा।

पेंशन, भविष्य निधि आदि

35—(1) अध्यापकों को किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा संचालित किसी परीक्षा के संबंध में किये गये किन्हीं कर्तव्यों के लिए पारिश्रमिक के संदाय संबंधी शर्तें वही होंगी जो विहित की जाएं।

अध्यापकों के लिए अनुज्ञेय अतिरिक्त पारिश्रमिकीय कार्य की सीमायें

(2) कोई अध्यापक अध्यापन संबंधी कर्तव्यों या किन्हीं परीक्षा संबंधी कर्तव्यों से भिन्न कर्तव्यों वाला एक से अधिक पारिश्रमिकीय पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण—शब्द “पारिश्रमिकीय पदों” में किसी छात्रावास के प्रोवोस्ट, वार्डन या अधीक्षक, प्रॉक्टर, क्रीड़ाधीक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सम्मिलित हैं।

36—(1) धारा 33 में निर्दिष्ट किसी नियुक्ति के संविदा से उठने वाला कोई विवाद माध्यस्थतम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, संबंधित अधिकारी या अध्यापक द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य (जो संयोजक का काम करेगा) सम्मिलित होंगे।

माध्यस्थतम अधिकरण

(2) यदि किसी कारणवश अधिकरण के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाए तो उस रिक्ति की पूर्ति के लिये उपयुक्त व्यक्ति या संबंधित निकाय उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेगा, और अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां उस प्रक्रम से जारी रखी जा सकती है, जिस प्रक्रम पर रिक्ति की पूर्ति की जाय।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा और उस पर किसी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी।

(4) माध्यस्थम अधिकरण की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी:—

(क) अपनी प्रक्रिया विनियमित करना;

(ख) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को पुनर्नियुक्ति करने का आदेश देना; और

(ग) संबंधित अधिकारी या अध्यापक को, ऐसी आय की कटौती करने के पश्चात् जो उसे सेवा से निलंबित होने, हटाये जाने, पदच्युत किये जाने अथवा समाप्त किये जाने के दौरान अन्यथा प्राप्त हुई हो, वेतन दिलाना।

(5) माध्यस्थम से सम्बद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट कोई बात इस धारा के अधीन माध्यस्थम पर लागू न होगी।

(6) किसी न्यायालय में कोई वाद या कार्यवाही किसी ऐसी बात के सम्बन्ध में नहीं की जाएगी जो उपधारा (1) द्वारा माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किये जाने के लिये अपेक्षित हो :

परन्तु उपधारा (3) में निर्दिष्ट अधिकरण का प्रत्येक विनिश्चय प्रादेशिक अधिकारितायुक्त निम्नतम न्यायालय द्वारा निष्पादनीय होगा मानों वह उक्त न्यायालय की कोई डिक्री हो।

अध्याय—सात

विश्वविद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारिवृंद की भर्ती और उनकी सेवा शर्तें

37—(1) विभिन्न सेवाओं में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती और पदोन्नति, परिनियमावली में यथा विहित भर्ती बोर्ड या पदोन्नति समितियों की सिफारिशों पर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेगी।

शिक्षणेत्तर
कर्मचारिवृंद की
सेवा शर्तें

(2) सेवाओं की सदस्य संख्या और उनमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या वही होगी, जैसा कि कार्य परिषद द्वारा अवधारित किया जाय और सरकार द्वारा समय—समय पर अनुमोदित किया जाय।

(3) आयु अवधारण और सेवा या अनुभव काल की गणना, उस भर्ती वर्ष, जो प्रत्येक वर्ष के 01 जुलाई से प्रारम्भ हो, के 01 जुलाई को की जायेगी।

(4) विभिन्न पदों आदि पर सीधी भर्ती या पदोन्नति हेतु आयु, न्यूनतम अर्हता, अनुभव, आरक्षण और अन्य सेवा शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय;

(5) रिक्त अनुमोदित पदों के सापेक्ष सरकार के निदेशों के अनुसार कर्मचारीगण को बाह्य स्रोतित किया जा सकता है।

अध्याय—आठ

परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम

38—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिये उपबन्ध किये जायेंगे:—

परिनियम

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियाँ और उनके कर्तव्य;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यों का नाम निर्देशन, नियुक्ति तथा पदावधि, और उनकी सदस्यता में रिक्तियों का भरा जाना और इन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय, जिनके लिए उपबन्ध करना आवश्यक हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य;

(घ) विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अन्य अध्यापकों का वर्गीकरण एवं भर्ती (न्यूनतम अर्हता और अनुभव सहित) उनके द्वारा विद्या संबंधी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट का रखा जाना और उनके द्वारा अनुपालनीय आचरण-नियम और उनकी परिलब्धियों तथा सेवा की अन्य शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं);

(ङ) विश्वविद्यालय के अधीन अन्य पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती (जिसमें न्यूनतम अर्हता और अनुभव सम्मिलित है) और उनकी परिलब्धियाँ एवं उनकी सेवा शर्तें (जिनमें अनिवार्य सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित अन्य उपबन्ध भी सम्मिलित हैं);

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों की प्रसुविधा के लिए नयी पेंशन स्कीम या भविष्य निधि का गठन अथवा बीमा स्कीम की स्थापना;

(छ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का संस्थित किया जाना;

(ज) मानद उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(झ) उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशेष उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ञ) संकायों की स्थापना, उनका समामेलन, उत्सादन और पुनर्गठन;

(ट) संकायों में अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ठ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों की स्थापना, उनका उत्सादन और पुनर्गठन;

(ड) विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज के वैतनिक कर्मचारियों (जो अध्यापक नहीं हैं) की संख्या , न्यूनतम अर्हतायें, अनुभव, परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें, जिनमें सेवानिवृत्ति की आयु और अनिवार्य सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबन्ध सम्मिलित हैं और उनके सेवा अभिलेख की रचना और अनुरक्षण;

(ढ) छात्रवृत्तियों, अधिछात्रवृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों को संस्थित करना;

(ण) दीक्षान्त समारोह, यदि कोई हो, आयोजित करना;

(त) ऐसी शर्तें, जिनके अधीन महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के विशेषाधिकार प्रदान किए जा सकते हैं और ऐसी शर्तें, जिनके अधीन ऐसा कोई विशेषाधिकार वापस लिया जा सकता है;

(थ) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के प्रबंध तंत्र को मान्यता प्रदान करना;

(द) अन्य सभी विषय जो इस अधिनियम द्वारा परिनियमों में उपबन्धित किये जाने हों या किये जा सकेंगे।

39—(1) विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली सरकार द्वारा, अधिसूचना के माध्यम से बनायी जायेगी।

परिनियमावली कैसे बनायी जायेगी

(2) कार्य परिषद नई या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकेगी या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन या उसे निरसित कर सकेगी।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठनों को प्रभावित करने वाली किसी परिनियमावली के प्रारूप का प्रस्ताव तब तक नहीं करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को उस प्रस्ताव पर अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दे दिया गया हो और इस प्रकार अभिव्यक्त कोई राय लिखित रूप में होगी तथा उसे कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) प्रत्येक नयी परिनियमावली या किसी परिनियमावली में किया गया परिवर्द्धन या किसी परिनियमावली में किया गया संशोधन या निरसन, कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जायेगा जो उस पर अपनी अनुमति दे सकेगा अथवा अपनी अनुमति रोक सकता है अथवा उस पर अग्रतर विचार करने के लिए कार्य परिषद को भेज सकेगा।

(5) कार्य परिषद द्वारा पारित कोई परिनियमावली, उस दिनांक से, जब कुलाधिपति द्वारा अनुमति दी जाए अथवा ऐसे पश्चात्तर्वर्ती दिनांक से जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, प्रभावी होगी।

(6) पूर्ववर्ती उपधाराओं में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य नियामक प्राधिकरण के किसी सुझाव या सिफारिश पर या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए विद्या, अध्यापकों, छात्रों या अन्य कर्मचारिवृंद के हित में अपने किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिए कार्य परिषद से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली में संशोधन करने या उसे निरस्त करने की अपेक्षा कर सकती है और यदि कार्य परिषद ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहती है तो सरकार कुलाधिपति की सहमति से नये या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमावली का संशोधन या निरसन कर सकती है।

(7) कार्य परिषद को सरकार द्वारा उपधारा (6) के अधीन बनायी गयी परिनियमावली को संशोधित या निरस्त करने या ऐसी परिनियमावली से संगत नई या अतिरिक्त परिनियमावली बनाने की शक्ति होगी।

40—(1) इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे जिनके लिए इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या अध्यादेशों द्वारा किये जायें।

अध्यादेश

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों के लिये उपबन्ध किये जायेंगे, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालयों में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबन्धी विशेष उपाधियों के लिए अधिकथित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम;

(ग) वे शर्तें, जिनके अधीन छात्रों को विश्वविद्यालय की परीक्षाओं और उपाधियों में प्रविष्ट किया जायेगा तथा वे ऐसी उपाधियाँ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे;

(घ) छात्रवृत्तियाँ, अधिछात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, निर्धन छात्रवृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने के लिये शर्तें;

(ङ) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(ड) विश्वविद्यालय में छात्रों के निवास तथा विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित छात्रावासों के प्रबंध की शर्तें;

(च) ऐसे छात्रावासों, जो विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित न हों, की मान्यता और प्रबंध;

(छ) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाये रखना और ऐसे दण्ड की व्यवस्था करना, जिसमें अनुशासन भंग करने अथवा ज्येष्ठ छात्रों द्वारा नये छात्रों की हिंसात्मक या अशिष्ट रैगिंग के लिये निलम्बन, निष्कासन या निर्बंधन सम्मिलित हैं;

(ज) फीस, जो विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन हेतु प्रभारित की जाय;

(झ) परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अनुसीमकों, अन्तरीक्षकों तथा सारणीकारों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन;

(ट) विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित व्यक्तियों को दिये जाने वाले पारिश्रमिक तथा भत्ते, जिनमें यात्रा और दैनिक भत्ते सम्मिलित हैं; और

(ठ) अन्य सभी विषय, जिनके लिये इस अधिनियम या परिनियमावली द्वारा उपबंध किये जाने हों या अध्यादेशों द्वारा किए जाएं;

41—(1) अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाये जायेंगे और कुलाधिपति को उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे। **अध्यादेश कैसे बनाये जायेंगे**

(2) कार्य परिषद समय-समय पर नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकती है अथवा उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों में संशोधन या निरसन कर सकती है:

परन्तु ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायेगा,—

(क) जिससे छात्रों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े या जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के समतुल्य मान्यता दी जाने वाली परीक्षाएँ अथवा विश्वविद्यालय की उपाधियों, पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये धारा 25 की उपधारा (1) में उल्लिखित अर्हताओं को विहित करें, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप, विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ख) जिससे परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों, तथा रीति और उनके कर्तव्यों तथा परीक्षाओं या किसी ऐसे पाठ्यक्रम के संचालन या उनके मानक पर प्रभाव पड़े जो कि संबंधित संकाय के प्रस्ताव के अनुसार न हो और जब तक कि ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो; या

(ग) जिससे विश्वविद्यालयों के अध्यापकों की संख्या, अर्हताओं तथा परिलब्धियों अथवा विश्वविद्यालय की आय या व्यय पर प्रभाव पड़े जब तक कि उसका प्रारूप सरकार द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो।

(3) कार्य परिषद को उपधारा (2) के अधीन विद्या परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप को संशोधित करने की शक्ति नहीं होगी किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकेगी या वह उसे विद्या परिषद को पूर्णतया अथवा अंशतः पुनः विचारार्थ किसी ऐसे संशोधनों के साथ वापस कर सकेगी जिनका कार्य परिषद सुझाव दे।

(4) कार्य परिषद द्वारा बनाये गये सभी अध्यादेश, ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगे जैसा कि वह निदेश दे और कुलाधिपति को यथाशक्य शीघ्र प्रस्तुत किये जायेंगे।

(5) कुलाधिपति किसी समय उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेशों से भिन्न अध्यादेशों को अननुज्ञात करने को कार्य परिषद को संज्ञापित कर सकेगा और कार्य परिषद को ऐसे अननुज्ञात करने की सूचना की प्राप्ति के दिनांक से ऐसे अध्यादेश, शून्य हो जायेंगे।

(6) कुलाधिपति यह निदेश दे सकेंगे कि उपधारा (2) के परन्तुक के खण्ड (ग) में निर्दिष्ट अध्यादेश से भिन्न किसी अध्यादेश का प्रवर्तन, तब तक निलम्बित रहेगा जब तक उसे अननुज्ञात करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने का अवसर न मिला हो। इस उपधारा के अधीन निलम्बन का कोई आदेश ऐसे आदेश के दिनांक से एक मास की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा।

42—(1) इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण या अन्य निकाय, निम्नलिखित के लिए विनियम बना सकेगा:—

(क) अपनी बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ख) ऐसे समस्त विषयों का उपबन्ध करना, जो इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा विनियमों से उपबन्धित किये जाने हों; और

(ग) किसी ऐसे विषय का उपबन्ध करना, जिसका संबंध केवल ऐसे प्राधिकरण या निकाय से हो और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमावली और अध्यादेशों में उपबन्ध न किये गये हों।

(2) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय द्वारा बनाये गये विनियमों में उसके सदस्यों की बैठकों के दिनांक और उनमें किये जाने वाले कार्य की सूचना देने तथा ऐसी बैठकों की कार्यवाही का अभिलेख रखने का उपबन्ध होगा।

(3) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय को यह निदेश दे सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय द्वारा बनाये गये किसी विनियम को निदेशों में यथा विनिर्दिष्ट रूप में रद्द कर दे या उसमें संशोधन कर दे और तदोपरान्त ऐसा प्राधिकारी या निकाय तदनुसार विनियम को रद्द करेगा अथवा उसमें संशोधन करेगा;

(4) विद्या परिषद, अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा, उपाधि या डिप्लोमा के पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने के लिये विनियम, संबन्धित संकाय बोर्ड द्वारा उसका प्रारूप प्रस्तावित किये जाने के पश्चात् ही बना सकेगा।

(5) विद्या परिषद के पास उपधारा (4) के अधीन संकाय बोर्ड द्वारा प्रस्तावित किसी प्रारूप में संशोधन अथवा उसे अस्वीकार करने की शक्ति नहीं होगी, किन्तु वह उसे बोर्ड को अपने सुझावों के साथ अग्रतर विचार करने के लिये वापस कर सकेगी।

अध्याय— नौ

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा

43—विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट, कार्य परिषद के निदेशों के अधीन तैयार की जायेगी। **वार्षिक रिपोर्ट**

44—(1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा तुलनपत्र, कार्य परिषद के निदेश के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय द्वारा प्रोद्भूत समस्त धनराशि, और ऐसी समस्त धनराशि, जिनका वितरण अथवा संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखाओं में प्रविष्ट की जायेगी। **लेखा तथा संपरीक्षा**

(2) वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र की एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जायेगी जिससे उनकी संपरीक्षा की जायेगी।

(3) सम्परीक्षित वार्षिक लेखाओं और तुलनपत्र को मुद्रित किया जायेगा और उनकी प्रतियाँ, संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतियों के साथ कार्य परिषद द्वारा सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) कार्य परिषद ऐसे दिनांक के पूर्व, जो विहित किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(5) व्यय की प्रत्येक नई मद, जो यथा विहित धनराशि से अधिक हो, जिसे बजट में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित हो, कार्य परिषद द्वारा वित्त समिति को निर्दिष्ट की जायेगी जो उस पर अपनी सिफारिश कर सकेगी।

(6) कार्य परिषद, जो वित्त समिति की सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् बजट का अन्तिम रूप से अनुमोदन करेगी।

(7) कुलपति या कार्य परिषद के लिये कोई व्यय उपगत करना वैध न होगा—

(क) जो या तो बजट में मंजूर न हो या बजट मंजूर होने के पश्चात् सरकार या भारत सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी अन्तर्राष्ट्रीय संगठन या फाउन्डेशन द्वारा विश्वविद्यालय को निधियाँ अनुदानित किये जाने की दशा में ऐसे अनुदान के निबन्धनों के अनुसार न हो:

परन्तु यह कि धारा 13 की उपधारा (7) में किसी बात के होते हुये भी, अग्निकाण्ड, बाढ़, अतिवृष्टि अथवा अन्य आकस्मिक अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों में कुलपति एक लाख रुपये से अनधिक ऐसा अनावर्ती व्यय, जो बजट में मंजूर न किया गया हो, उपगत कर सकेगा और उसे ऐसे सम्पूर्ण व्यय के संबंध में तत्काल सरकार को सूचित करना होगा;

(ख) जो इस अधिनियम के अधीन दिये जाने हेतु तात्पर्यित कुलाधिपति या सरकार के किसी आदेश का विरोध करने के लिये किसी मुकदमे के सम्बन्ध में हो।

45—(1) धारा 10 के खण्ड (ख) से (ज) में से किसी खण्ड में विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी, विश्वविद्यालय की किसी धनराशि या सम्पत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन हेतु अधिभार का दायी होगा, यदि ऐसे हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन सीधे उसकी उपेक्षा या अपचार के परिणामस्वरूप हुआ हो। **अधिभार**

(2) अधिभार की प्रक्रिया और ऐसी हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन में अन्तर्निहित धनराशि की वसूली की रीति ऐसी होगी जैसे विहित की जाय।

अध्याय — दस

विविध

46—(1) इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी परिनियमावली द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय विश्वविद्यालय के अधिकारी और विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के सदस्यगण यथासंभव निर्वाचन से भिन्न पद्धतियों से चुने जायेंगे।

प्राधिकरणों के अधिकारियों तथा सदस्यों की नियुक्ति की रीति

(2) जहां इस अधिनियम या परिनियमावली में चक्रानुक्रम से ज्येष्ठता अथवा अन्य अर्हता के अनुसार किसी आवेदन के लिये कोई उपबन्ध किया गया हो तो चक्रानुक्रम और ज्येष्ठता तथा अन्य अर्हतायें अवधारित करने की रीति वही होगी जो विहित की जाय।

(3) इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से यथा उपबन्धित के सिवाय, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय के निर्वाचन में खड़े होने के लिये पात्र न होगा।

47—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति को उसी रीति से भरा जायेगा जिस रीति से वह सदस्य, जिसकी रिक्ति भरी जानी हो, चुना गया हो और रिक्ति को भरने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकरण या निकाय का उस अवशिष्ट अवधि के लिये सदस्य होगा जिसके लिये, वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

(2) कोई व्यक्ति, जो अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य हो, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो अथवा बाहरी हो केवल तब तक ऐसे प्राधिकरण में अपना सीट धारित करता रहेगा, जब तक वह ऐसे निकाय का प्रतिनिधि बना रहेगा।

48—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय अथवा समिति की कोई कार्यवाही, केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि—

रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

- (क) उसमें कोई रिक्ति अथवा उसके गठन में कोई त्रुटि थी; या
- (ख) कार्यवाहियों में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है, जो ऐसा करने के लिए हकदार नहीं था; या
- (ग) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के नाम—निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी; या
- (घ) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता थी जिससे मामले के गुणावगुण पर कोई प्रभाव न पड़ता हो।

49—कार्य परिषद, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय की सदस्यता से इस आधार पर कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता से संबंधित ऐसे अपराध के लिये सिद्धदोष हुआ हो अथवा इस आधार पर कि वह कलंकात्मक आचरण का दोषी हो अथवा उसने ऐसी रीति से व्यवहार किया हो, जो विश्वविद्यालय के सदस्यों के लिये अशोभनीय हो, हटा सकती है और उन्हीं आधारों पर किसी व्यक्ति से विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या मंजूर की गयी कोई उपाधि या प्रमाण—पत्र वापस ले सकती है।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना

50—यदि कोई ऐसा प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या अन्य निकाय का सम्यक रूप से निर्वाचित या नियुक्त सदस्य रहा है या नहीं या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं (जिसके अन्तर्गत किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम, जो राज्य सरकार द्वारा या कुलाधिपति द्वारा बनाया या अनुमोदित किया गया परिनियम या अध्यादेश न हो, की विधिमान्यता से संबंधित कोई प्रश्न भी सम्मिलित है) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो उक्त विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायेगा और कुलाधिपति का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा :

कुलाधिपति को निदेश

परन्तु यह कि इस धारा के अधीन कोई निर्देश—

- (क) उस दिनांक के, जब प्रश्न प्रथम बार उठाया जा सकता था तीन मास से अधिक के पश्चात् ;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अधिकारी अथवा किसी व्यक्तित्व से भिन्न व्यक्तित्व द्वारा, नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि कुलाधिपति आपवादिक परिस्थितियों में—

(एक) पूर्वगामी परन्तुक में उल्लिखित अवधि की समाप्ति के पश्चात् स्वप्रेरणा पर कार्य कर सकेगा अथवा निदेश ग्रहण कर सकेगा;

(दो) जहां निर्दिष्ट विषय का संबंध निर्वाचन से संबंधित किसी विवाद से हो, और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्तियों की पात्रता संदेहास्पद हो तो ऐसा स्थगन आदेश दे सकेगा जिसे वह न्यायोचित और समीचीन समझे।

51—(1) विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो, तो ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प अथवा दस्तावेज अथवा रजिस्टर में प्रविष्टि की विद्यमानता, प्रथम दृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय तथा संव्यवहारों को साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायेगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती तो वह साक्ष्य में ग्राह्य होती।

विश्वविद्यालय का अभिलेख सिद्ध करने की रीति

(2) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी से, किसी ऐसी कार्यवाही में, जिसमें विश्वविद्यालय एक पक्षकार न हो, विश्वविद्यालय का कोई ऐसा दस्तावेज, रजिस्टर या अन्य अभिलेख, जिसकी अन्तर्वस्तुएं उपधारा (1) के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा सिद्ध की जा सकती हों, प्रस्तुत करने की अथवा उसमें अभिलिखित विषयों तथा संव्यवहारों को सिद्ध करने के लिए साक्षी के रूप में उपस्थित होने की तब तक अपेक्षा न की जायेगी, जब तक कि न्यायालय विशेष कारण से आदेश न दे।

52—कुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी और विश्वविद्यालय के अन्य कर्मचारीगण, जब इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्यरत हों या कार्यरत होना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

53—सरकार या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकरण या उसके निकाय के विरुद्ध उक्त अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली या अध्यादेशों के अनुसरण में किये गये अथवा किये जाने के लिए तात्पर्यित या आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

वाद का वर्जन

अध्याय — ग्यारह

संक्रमणकालीन उपबन्ध

54—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण, यथाशीघ्र इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार गठित किया जायेगा।

प्राधिकरण का गठन

(2) जब तक कि उपधारा (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का गठन न किया जाय, राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि कार्य परिषद से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रयोक्तव्य शक्तियाँ अथवा निर्वहन योग्य, कर्तव्यों तथा कृत्यों का प्रयोग अथवा निर्वहन किसके द्वारा और किस रीति से किया जायेगा।

55—(1) सरकार, कोई कठिनाईयां दूर करने के प्रयोजनार्थ यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध, ऐसी अवधि में जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसी अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, प्रभावी होंगे:

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष के पश्चात् ऐसा कोई आदेश नहीं किया जायेगा;

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि उक्त उपधारा में निर्दिष्ट कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसको दूर करना अपेक्षित नहीं था।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्थित जिला गोरखपुर में राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना करने का उपबन्ध करने के लिए एक विधि बनाने का विनिश्चय किया गया है।

उक्त विधेयक की मुख्य विशेषताएं नीचे यथा उल्लिखित हैं:-

(क) विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य आयुष विज्ञान, आयुष परिचर्या, पराचिकित्सा और अन्य विधाओं में ज्ञान का प्रसार और उसकी अभिवृद्धि करना है;

(ख) विश्वविद्यालय को निम्नलिखित के लिये सशक्त करना :-

(एक) सरकारी और साथ-ही-साथ निजी प्रबन्धकृत संस्थाओं को सम्बद्ध करना तथा उनकी परीक्षाएं संचालित करना और राज्य के कतिपय अन्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में संशोधन करके उनकी सम्बद्धता की शक्ति को समाप्त करना;

(दो) उसके चिकित्सालयों तथा निदान केन्द्रों को प्रशासित करना, उनका प्रबन्ध करना तथा उनपर नियंत्रण रखना;

(तीन) पारम्परिक तथा अभिनव क्षेत्रों में अनुसंधान को सुगम बनाना;

(चार) अध्यापकों तथा अन्य प्राविधिक एवं पराचिकित्सीय अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र स्थापित करना।

तदनुसार राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2020 पुरःस्थापित किया जाता है।